राजस्थान राज्य

बनाम

रोशन खान और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 79-80/2005)

15 जनवरी, 2014

[ए. के. पटनायक और ज्ञान सुधा मिश्रा, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860:

एसएस 376(2)(जी) और एस 366- सामूहिक बलात्कार-निचली अदालत द्वारा छह अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया-उच्च दोषमुक्ति द्वारा बरी-हुआःअभियोजन मामला कि छह अभियुक्तों ने अभियोजक पर सामूहिक बलात्कार किया था, उसके साक्ष्य और उसके पिता के साक्ष्य से स्थापित किया गया है, जैसा कि चिकित्सा साक्ष्य और एफ. एस. एल. रिपोर्ट द्वारा पुष्टि की गई है-उच्च निचली अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया गया है और निचली अदालत के सभी अभियुक्तों को आरोपित अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और उन्हें दो मामलों के तहत 10 साल आर. आई. और 4 साल आर. आई. की सजा सुनाई गई है। एस.376 (2) (जी), स्पष्टीकरण 1-सामूहिक बलात्कार-अनुमान-आयोजितः तत्काल मामले में चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार, चार व्यक्तियों ने अभियोजन पक्ष पर बलात्कार किया था-स्पष्टीकरण 1 से एस। 376(2)(छ) में कहा गया है कि जहां एक या एक से अधिक व्यक्तियों के समूह में एक महिला के साथ उनके समान इरादे को आगे बढ़ाने के लिए बलात्कार किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को उप-धारा के अर्थ के भीतर सामूहिक बलात्कार किया हुआ माना जाएगा-इसलिए, यह आवश्यक नहीं है कि अभियोजन पक्ष को पीड़ित पर प्रत्येक अभियुक्त द्वारा बलात्कार के पूर्ण कार्य का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए।

साक्ष्य अधिनियम, 1872:

एस.114-ए-एक सामूहिक बलात्कार में धारणा उल 376 (2) (जी),/पी. सी.-आयोजितःचूंकि अभियोजक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उसकी सहमति के बिना और जबरन यौन संबंध बनाए गए थे, इसलिए अदालत को यह धारणा बनानी होगी कि उसने अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उसके साथ किए गए यौन संबंध के लिए सहमति नहीं दी थी-बचाव पक्ष ने इस धारणा का खंडन करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है-इसलिए, उच्च न्यायालय यह नहीं मान सकता था कि ऐसी परिस्थितियां थीं जो यह दिखा सकें कि अभियोजक अपने दम पर चला गया था और इस आधार पर प्रतिवादियों को दंड संहिता, 1860-एस से बरी कर दिया गया था। 376(2)(जी)।

प्राथमिकी आर

सामूहिक बलात्कार-प्राथमिकी दर्ज करने में चार घंटे की देरी-आयोजितः सूचना देने वाले द्वारा देरी को पर्याप्त रूप से समझाया गया है। अभियुक्त-उत्तरदाता एन. ओ. एस. 1 से 6 तक पर भा.दं.सं. सी. की धारा 376 (2) (जी) और 366 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए इस आरोप पर मुकदमा चलाया गया कि घटना की रात में, वे एक 16 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर लड़की को एक सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। निचली निचली अदालत ने सभी छह अभियुक्तों को आरोपित अपराधों के लिए दोषी ठहराया और दोनों मामलों के तहत उनमें से प्रत्येक को 10 साल आर. आई. और 4 साल आर. आई. की सजा सुनाई। हालांकि, उच्च न्यायालय ने उन्हें दोनों आरोपों से बरी कर दिया।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 अभियोजक के पिता, मुखबिर (पीडब्लू-1) ने बयान दिया है कि उसके भाई की बेटी की शादी की तारीख आईडी1 थी और शाम के समय आईडी 2 पर उसकी बेटी

(अभियोजक), जो 14 साल की थी और मानसिक रूप से संतुलित नहीं थी, इलाके की महिलाओं को फोन करने गई थी और जब वह नहीं लौटी, तो वह अपने भाई द्वारा चलाए गए स्कूटर पर उसकी तलाश करने गया। उन्होंने एक पुरानी जीर्ण-शीर्ण इमारत के पास पांच लोगों को खड़े देखा, जो उन्हें देखकर भाग गए। जब वे अंदर गए, तो उन्होंने पाया कि अभियोजक रो रहा था और आरोपी 'ए' उसके ऊपर लेटा हुआ था और उसके साथ यौन संबंध बना रहा था। अभियोजक (पीडब्लू-2) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी छह व्यक्तियों ने उसकी सहमति के बिना और जबरन उसके साथ बलात्कार किया। पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के साक्ष्य कि सभी छह प्रतिवादी ने अभियोजक पर बलात्कार किया था, घटना के कुछ घंटों के भीतर पीडब्लू-1 द्वारा पुलिस को की गई शिकायत (Ext.P-1) से भी पुष्टि होती है, जैसा कि एस में प्रदान किया गया है। 157 साक्ष्य अधिनियम। पीडब्लू-7, डॉक्टर ने अभियोजक की चिकित्सकीय जांच के बाद राय दी है कि यह बताने के लिए कुछ भी नहीं था कि उसके साथ बलात्कार नहीं किया गया था। एफएसएल की रिपोर्ट अभियोजन मामले का समर्थन करती है। चिकित्सा साक्ष्य, इसलिए, पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के साक्ष्य की भी पुष्टि करते हैं कि अभियोजक और अभियुक्त व्यक्तियों के बीच यौन संबंध थे। [पैरा 10,11 और 14] [427-0-G; 428-8, D; 430-FG; 431-8-C]

1.2. साक्ष्य अधिनियम, 1872 की खंड 114 ए में स्पष्ट रूप से उप-खंडओं के खंड (जी) के तहत बलात्कार के लिए अभियोजन का प्रावधान है। (2) एस.376, भा.दं.सं. सी., जहां आरोपी द्वारा यौन संबंध साबित होता है और सवाल यह है कि क्या यह महिला की सहमति के बिना कथित बलात्कार किया गया था और वह अदालत के समक्ष अपने साक्ष्य में कहती है कि उसने सहमति नहीं दी थी, अदालत यह मान लेगी कि उसने सहमति नहीं दी थी। चूंकि अभियोजक (पीडब्लू-2) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यौन संबंध अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उसकी सहमति के बिना और जबरन किए गए

थे, इसलिए अदालत को यह धारणा बनानी होगी कि उसने अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उस पर किए गए यौन संबंध के लिए सहमति नहीं दी थी। बचाव पक्ष ने इस धारणा का खंडन करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है। इसलिए, उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित नहीं कर सकता था कि यह दिखाने के लिए परिस्थितियाँ थीं कि पीडब्लू-2 अपने दम पर चली गई थी और इस आधार पर प्रतिवादी को बरी कर दिया गया था। [पैरा 15] [431-डी-जी]

1.3. चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार, चार व्यक्तियों ने अभियोजक पर बलात्कार किया था। स्पष्टीकरण 1 से एस 376(2)(छ) भा.दं.सं. सी. में कहा गया है कि जहां एक या एक से अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी महिला के साथ बलात्कार किया जाता है, जो उनके सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे होते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को उप-धारा के अर्थ के भीतर सामूहिक बलात्कार किया हुआ माना जाएगा। इसलिए, इस न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां एक से अधिक व्यक्ति किसी पीड़िता के साथ बलात्कार करने के अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, यह आवश्यक नहीं है कि अभियोजन पक्ष को प्रत्येक अभियुक्त द्वारा बलात्कार के पूर्ण कार्य का प्रमाण प्राप्त करना चाहिए। [पैरा 16] [432-ए-सी]

ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य 2011 (7) एस. सी. आर. 1080 = (2011) 14 एस. सी. सी. 309, अशोक कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2003) 2 एस. सी. सी. 143, भूपिंदर शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 2003 (4) पूरक। एस. सी. आर. 792 = (2003) 8 एस. सी. सी. 551, प्रदीप कुमार बनाम संघ प्रशासन। 2003 (4) पूरक। एससीआर 792 = (2006) 10 एससीसी 608 और प्रिया पटेल बनाम मध्य प्रदेश राज्य। 2006 (3) पूरक। एस. सी. आर. 456 = (2006) 6 सेक. 263-पर निर्भर था।

1.4. पीडब्लू-1 ने अपने साक्ष्य में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने अपनी बेटी को सुबह लगभग 1 पूर्वाह्न आरोपी 'ए' के साथ घटना स्थल पर पाया और पांच अन्य आरोपी व्यक्तियों के भाग जाने के बाद, वे सुबह 2 पूर्वाह्न अपने घर लौट आए और सूर्योदय से पहले तक अपने घर पर रहे और उसके बाद पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने आगे कहा है कि रिपोर्ट दर्ज करने में सुबह 2 पूर्वाह्न से सुबह 6 पूर्वाह्न तक की देरी इस तथ्य के कारण थी कि उनकी पत्नी बीमार थी और वह भी डर गए थे और पुलिस स्टेशन जाने के लिए कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। एस. एच. ओ. ने अपने साक्ष्य में कहा है कि आई. डी. 2 पूर्वाह्न सूचना देने वाला पुलिस थाने में पेश हुआ और सुबह 6 पूर्वाह्न उसके सामने एक लिखित रिपोर्ट (आई. डी. 1) पेश की। इस प्रकार, पी. डब्ल्यू.-1 द्वारा सुबह 6 पूर्वाह्न रिपोर्ट (आई. डी. 1) दायर की गई और सुबह 2 पूर्वाह्न से सुबह 6 पूर्वाह्न तक की अवधि को उसके साक्ष्य में पूर्वाह्न्यास रूप से समझाया गया है कि वह अपनी पत्नी को सूर्योदय तक अकेला नहीं छोड़ सकता था। कोई भी पिता झूठी शिकायत दर्ज नहीं कराएगा कि उसकी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। उच्च न्यायालय को प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के आधार पर अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह नहीं करना चाहिए था। [पैरा 17] [432-एफ-एच; 433 ए-बी, सी-0]

1.5. इस प्रकार, उच्च न्यायालय का निर्णय अभिलेख पर साक्ष्य के विपरीत है और इस प्रकार, खारिज कर दिया जाता है। भा.दं.सं. सी. की धारा 366 और 376 (2) (जी) के तहत अपराधों के प्रतिवादी को दोषी ठहराने वाले निचली निचली अदालत के फैसले को बहाल किया जाता है और विचारण निचली अदालत द्वारा प्रतिवादी पर दो अपराधों के लिए लगाए गए दंड को बनाए रखा जाता है। [पैरा 18] [433-ई-एफ]

बावांट सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (1987) 2 एस. सी. सी. 27; एच. पी. बनाम राज्यज्ञान चंद 2001 (3) एस. सी. आर. 247 = (2001) 6 एस. सी. सी.

71 टी. यू./शीलदास कनोलकर बनाम गोवा राज्य 2003 सी. (4) सप्लीमेंट। एस. सी. आर. 978 = (2003) 8 एस. सी. सी. 590; राजस्थान राज्य बनाम एन. के. 2000 (2) एस. सी. आर. 818 = (2000) 5 एस. सी. सी. 30; और राजस्थान राज्य बनाम शेरा राम 2011 (15) एस. सी. आर. 485 = (2012) 1 सेक 602-उद्धृत।

मामला कानून संदर्भः

1987 (2) धारा 21 उद्धृत पैरा 6

2001 (3) एस. सी. आर. 247 उद्धृत पैरा 7

2003 (4) पूरक एस. सी. आर. 978 उद्धृत पैरा 7

2000 (2) एस. सी. आर. 818 उद्धृत पैरा 7

2011 (15) एस. सी. आर. 485 उद्धृत पैरा 9

2011 (7) एस. सी. आर. 1080 पैरा 16 पर निर्भर था।

2003 (2) धारा 143 पैरा 16 पर निर्भर थी।

2003 (4) पूरक एस. सी. आर. 792 पैरा 16 पर निर्भर था।

2006 (3) पूरक एस. सी. आर. 456 पैरा 16 पर निर्भर था।

आपराधिक अधिकार क्षेत्र न्यायनिर्णयः दाण्डिक अपीलीय सं 79-80/2005

उच्च न्यायालय, जोधपुर राजस्थान के एस. बी. दाण्डिक अपीलीय सं 765 और 743/2000 में न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 21.11.2003 से।

अपीलकर्ता की ओर से डॉ. मनीष सिंघवी, एम. जी., अमित लुभाया, मिलिंद कुमार।

प्रतिवादीओं के लिए मुकेश शर्मा, रामेश्वर प्रसाद गोयल, सिद्धार्थ दवे (ए. सी.), जेमतीबेन आओ।

न्यायालय का निर्णय ए. के. पटनायक, जे. द्वारा दिया गया था।

1. ये स्पाइस के माध्यम से अपीलें हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') की खंड 366 और 376 (2) (जी) के तहत दंडनीय अपराधों के प्रतिवादी को दोषी ठहराने वाले राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के फैसले के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अनुमति तथ्य।

2. तथ्य बहुत संक्षेप में यह है कि 28.04.1999 पर रूलिराम ने हनुमानगढ़ जिले के भद्रा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया हैः उनके भाई ज्ञान सिंह की बेटी की शादी थी जिसके लिए उनके द्वारा 27.04.1999 पर एक दावत का आयोजन किया गया था। उनकी 15-16 वर्ष की बेटी, जो थोड़ी कमजोर सोच वाली थी, गायब हो गई। जब वह काफी देर तक नहीं लौटी तो उसने और अन्य लोगों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। लगभग 9 बजे, एक दूधवाले ने उसे बताया कि उसने छह लड़कों को एक लड़की को कल्याण भूमि की ओर ले जाते देखा है। आईडी1 पर लगभग 1 पूर्वाहन, जब रूलिराम स्कूटर पर था और ज्ञान सिंह अभी भी अपनी बेटी की तलाश कर रहा था, तो उसने भेड़ और ऊन विभाग के पुराने जीर्ण-शीर्ण कार्यालय भवन के पास स्कूटर की रोशनी में पांच लड़कों को देखा और सभी पांचों, स्कूटर की रोशनी देखकर भाग गए। जब वे पुरानी इमारत में गए तो उन्होंने अकबर को अपनी बेटी के साथ यौन संबंध बनाते हुए पाया और वह चिल्ला रही थी। उन्होंने अकबर को पकड़ लिया जिसने बाद में उन्हें सूचित किया कि बाकी पांचों ने भी उसकी बेटी के साथ यौन संबंध बनाए थे और वे बाकी पांच व्यक्तियों को जानते थे। पुलिस ने भा.दं.सं. सी. की धारा 147 और 376 के तहत मामला दर्ज किया और जांच की और छह प्रतिवादी के

खिलाफ भा.दं.सं. सी. की धारा 376/34 के तहत आरोप-पत्र दायर किया और मुकदमा चलाया गया।

3. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नोहर कैंप, भद्रा के समक्ष मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों से पूछताछ की। रूलिराम की जांच पीडब्लू-1 के रूप में की गई, उनकी बेटी (अभियोजक) की जांच पीडब्लू-2 के रूप में की गई, और डॉ. रामलाल, जिन्होंने अभियोजक की चिकित्सकीय जांच की थी, की जांच की गई।

पीडब्लू-7 और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को Ext.P-39 के रूप में चिह्नित किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-7 और आई. डी. 2 के साक्ष्य पर भरोसा किया और भा.दं.सं. सी. की खंड 376 (2) (जी) और खंड 366 के तहत छह प्रतिवादी को दोषी ठहराया और सजा के सवाल पर उन्हें सुनने के बाद, उन्हें दस-दस साल के लिए कठोर कारावास और 5,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, चूक में भा.दं.सं. सी. की खंड 376 (2) (जी) के तहत अपराध के लिए दो-दो महीने के कठोर कारावास और चार-चार साल के लिए कठोर कारावास और 3,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि दोनों अपराधों के लिए सजाएं एक साथ चलेंगी और आरोपी व्यक्तियों द्वारा जुर्माना जमा करने पर, अभियोजक को 1,000/- का मुआवजा दिया जाएगा।

4. प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील दायर की और उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में कहा कि अभियोजक (पीएन-2) का बयान विश्वसनीय नहीं था और डॉ. राम लाल (पीडब्लू-7) का साक्ष्य कुछ मामलों में अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि नहीं करता था। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि रूलिराम (पीडब्लू-1) द्वारा दिए गए साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि अभियोजक की आयु केवल 14 वर्ष थी और उसकी आयु 19 वर्ष तक हो सकती है और ऐसी परिस्थितियाँ थीं

जिनसे पता चलता है कि वह स्वयं प्रतिवादी के साथ गई थी। उच्च न्यायालय का यह भी विचार था कि रूलिराम (पीडब्लू-1) की ओर से सुबह 1 पूर्वाहन जब यह घटना उनके संज्ञान में आई तो उस पर प्राथमिकी दर्ज करने में देरी ने अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह पैदा कर दिया। उच्च न्यायालय ने तदनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के फैसले को दरकिनार कर दिया, अपीलों को स्वीकार कर लिया और सभी छह प्रतिवादी को आरोपों से बरी कर दिया।

पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ता की दलीलें:

5. राज्य के विद्वान अधिवक्ता डॉ. मनीष सिंघवी ने कहा कि उच्च न्यायालय को पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के साक्ष्य पर अविश्वास नहीं करना चाहिए था क्योंकि इन गवाहों और आरोपी व्यक्तियों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-7 के साक्ष्य का भी उल्लेख किया। एफ. एस. एल. रिपोर्ट (Ext.P-39) यह दिखाने के लिए कि छह अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा सामूहिक बलात्कार का मामला उचित संदेह से परे स्थापित किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय यह नहीं मान सकता था कि ऐसी परिस्थितियाँ थीं जो यह सुझाव देती हैं कि अभियोजक आरोपी व्यक्तियों के साथ अपने दम पर जा सकता था। उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की खंड 114ए पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया है कि जहां आरोपी द्वारा यौन संभोग शुष्क साबित होता है, सवाल यह है कि क्या यह कथित महिला की सहमति के बिना बलात्कार किया गया था और वह अदालत के समक्ष अपने साक्ष्य में कहती है कि उसने सहमति नहीं दी थी, अदालत यह मान लेगी कि उसने सहमति नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की खंड 114ए के तहत इस धारणा को नजरअंदाज कर दिया है।

6. डॉ. सिंघवी ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय को प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के आधार पर अभियोजन पक्ष की कहानी के बारे में संदेह पर विचार नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कोई भी पिता अपनी बेटी पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहेगा। उन्होंने बलवंत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य ((1987) 2 एस. सी. सी. 27) मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें इसी तरह का तर्क कि अभियोजक के पिता ने आरोपी के साथ पिछली दुश्मनी के कारण एफ. आई. आर. दर्ज की थी, इस आधार पर खारिज प्राथमिकी दिया गया था कि अभियोजक का पिता आरोपी द्वारा बलात्कार के मामले में अपनी बेटी को गलत तरीके से शामिल नहीं प्राथमिकीेगा।

7. डॉ. सिंघवी ने अंत में कहा कि इस मामले में अभियोजक एक मानसिक रूप से कमजोर लड़की थी और यौन दुरुपयोग की चपेट में थी और इसलिए, उच्च न्यायालय को मामले का फैसला करते समय संवेदनशील होना चाहिए था। उन्होंने एच. पी. बनाम राज्य मामले में इस न्यायालय के फैसलों का हवाला दिया। ज्ञान चंद [(2001) 6 धारा 71] के साथ-साथ तुलसीदास कनोलकर बनाम गोवा राज्य [(2003) 8 एस. सी. सी. 590] में इस निवेदन के समर्थन में। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में निचली अदालत ने प्रतिवादी को भा.दं.सं. सी. की धारा 366 और 376 (2) (जी) के तहत सही दोषी ठहराया था, लेकिन उच्च निचली अदालत ने प्रतिवादी की दोषसिद्धि को उलट दिया और उन्हें आरोपों से बरी कर दिया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि लगभग इसी तरह के तथ्यों पर राजस्थान राज्य बनाम एन. के. [(2000) 5 एस. सी. सी. 30] में इस निचली अदालत ने उच्च निचली अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया है और निचली अदालत द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि को बहाल कर दिया है।

8. जवाब में, प्रतिवादी संख्या 1,2,3,4 और 6 के विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश शर्मा ने प्रस्तुत किया कि डॉ. रामलाल (पीडब्लू-7) को अभियोजक के निजी अंगों पर कोई चोट नहीं मिली है और उन्होंने केवल एक्जिमा के कुछ निशान पाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पीडब्लू-1 ने केवल यह कहा है कि स्कूटर की रोशनी की मदद से, उसने पांच लोगों को भागते हुए देखा, लेकिन वह इन पांच व्यक्तियों की ठीक से पहचान नहीं समर्थ है, अर्थात्, प्रतिवादी संख्या 1,2,3,4 और 6। उन्होंने कहा कि चूंकि उन्होंने केवल अकबर (प्रतिवादी संख्या 5) को अभियोजक के साथ यौन संबंध रखते हुए पाया था, इसलिए भा.दं.सं. की खंड 376 (2) (जी) के तहत सामूहिक बलात्कार का कोई मामला नहीं बनता है।

9. प्रतिवादी नंबर 5 के न्यायालय मित्र श्री सिद्धार्थ दवे ने कहा कि अभियोजन पक्ष की कहानी कि अभियोजक एक मानसिक रूप से कमजोर लड़की थी, साबित नहीं हुई है। उन्होंने तर्क दिया कि, इसके विपरीत, डॉक्टर (पीडब्लू-7) ने राय दी है कि अभियोजक की मानसिक स्थिति और संतुलन सामान्य थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्राथमिकी वास्तव में 11.00 सुबह 28.04.1999 पर दर्ज की गई थी और 28.04.1999 पर सुबह 6 पूर्वाह्न तक दर्ज की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि यह हेरफेर अभियोजन पक्ष की कहानी पर गंभीर संदेह पैदा करता है कि अभियोजक पर बलात्कार किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि डॉ. रामलाल (पीडब्लू-7) ने अभियोजक की जांच में पाया है कि एक पोस्टीरियर पेरिनिया था!24 घंटे के भीतर 1/4 "x 1/8" x 1/8 "आकार का फटना और यह भी राय दी थी कि यह चोट किसी कठोर सतह पर गिरने के कारण हो सकती है और इसलिए, अकबर द्वारा बलात्कार का मामला उचित संदेह से परे स्थापित नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले के तथ्यों पर उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण प्रशंसनीय है और संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने इस निवेदन के समर्थन में राजस्थान राज्य बनाम शेरा राम [(2012) 1 एस. सी. सी. 602] में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

न्यायालय के निष्कर्ष

10. हमने सूचना देने वाले (पीडब्लू-1) के साक्ष्य का अध्ययन किया है। उन्होंने कहा है कि 28.04.1999 उनके भाई ज्ञान की बेटी मंजू की शादी की तारीख थी और 27 को शाम के समय उनकी बेटी (अभियोजक), जो 14 साल की थी और मानसिक रूप से संतुलित नहीं थी, महिलाओं को फोन करने गई थी।

इलाकाई लेकिन वापस नहीं आया। उसने पूरे गाँव की तलाशी ली और उसके बाद वह अपने भाई ज्ञान सिंह द्वारा चलाई गई स्कूटर पर गाँव राजपुरा की ओर चला गया और रास्ते में एक दूधवाले ने उन्हें बताया कि छह लड़के एक लड़की का हाथ पकड़कर उसे श्मशान की ओर ले जा रहे हैं। वे श्मशान घाट में अभियोजक की तलाश में गए लेकिन उसे वहां नहीं मिला। इसके बाद, उन्होंने स्कूटर को गांव मोतीपुरा की ओर मोड़ दिया और उन्होंने पाया कि भेड़िया दफ्तार (एक पुरानी जीर्ण-शीर्ण इमारत) के पास कीकर के पेड़ों के झुंड में पांच लोग खड़े थे और उन्हें देखकर पांच लोग भाग गए। जब वे जीर्ण-शीर्ण इमारत के अंदर गए तो उन्होंने पाया कि अभियोजक रो रहा था और अकबर उसके ऊपर लेटा हुआ था और उसके साथ यौन संबंध बना रहा था। पीडब्लू-1 ने यह भी कहा है कि भागने वाले पांच व्यक्ति रोशन, जंगशेर, याकूब, शफी और कादर हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उपरोक्त सभी छह व्यक्ति उनके मोहा/ला (इलाके) के निवासी हैं और अदालत में मौजूद थे। पीडब्लू-1 ने आगे कहा है कि जब तक वे भेड1ए दफ्तार पहुंचे, तब तक लगभग 1 पूर्वाह्न का समय था और वह अभियोजक और अकबर को पुलिस स्टेशन ले गया और 6 पूर्वाह्न शिकायत (Ext.P-1) दर्ज कराई।

11. हमने अभियोजक (पीडब्लू-2) के साक्ष्य का भी अध्ययन किया है। उसने कहा है कि जब उसके चाचा ज्ञान की बेटी की शादी होनी थी, तो वह शाम को अपने घर से महिलाओं को गाने के लिए बुलाने के लिए बाहर गई थी और रास्ते में वह अकबर से मिली, जिसने उसे बताया कि उसके चाचा उसे ढूंढ रहे थे। फिर वह अकबर के साथ आगे बढ़ी और रेलवे क्रॉसिंग के पास जांगशेर से मिली, जिसने उसे यह भी बताया कि उसके चाचा उसे ढूंढ रहे हैं। फिर वह चलने लगी और अकबर और जंगशेर ने उसका पीछा किया और कुछ समय बाद उसने शफी और याकूब को पाया और चारों लोग उसका पीछा करने लगे और कुछ समय बाद उसने कादर और रोशन को देखा और सभी छह लोग उसे सड़क पर एक पुल पर ले गए और वहाँ से वे उसे खेत में ताली के पेड़ के पास ले आए। इसके बाद, सभी छह लोगों ने उसे जबरदस्ती ताली के पेड़ के नीचे गिरा दिया और उसके सा/वार को हटा दिया, उसे पकड़ लिया और उसे दो-तीन खेतों की दूरी पर ले गए और फिर एक झोपड़ी में ले गए। फिर वे उसे भेड़िया दफ्तार ले गए जहाँ उन्होंने उसके साथ यौन संबंध भी बनाए और जब अकबर उसके साथ बलात्कार कर रहा था, तो पीडब्लू-1 और उसके चाचा आए और बाकी पांच लोग भाग गए। उसने कहा है कि ये सभी छह आरोपी व्यक्ति उसके मोहल/ए (इलाके) के हैं और वे अदालत में मौजूद थे। उसने अदालत में छह अभियुक्तों की पहचान भी की है। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी छह व्यक्तियों ने उसकी सहमति के बिना और जबरन उसके साथ बलात्कार किया।

12. हमने डॉ. रामलाल (पीडब्लू-7) के साक्ष्य को भी पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अभियोजक की जांच की है और चिकित्सा जांच रिपोर्ट (Ext.P-15) तैयार की है और उन्हें उसके छिपे हुए हिस्सों, स्तन, जांघों और अग्र-भुजा पर चोट का कोई निशान नहीं मिला है। उसने आगे कहा है कि उसका हाइमेन पहले से ही टूट चुका था और एक पोस्टीरियर पेरिनिया था।24 घंटे के भीतर 1/4 "x 1/8" x 1/8 "आकार का फटना।

उनकी राय है कि अभियोजक यौन संभोग का आदी था और यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं था कि उसका बलात्कार नहीं किया गया था, लेकिन शुक्राणुओं की उपस्थिति ए का पता लगाने के लिए योनि के स्वाब और स्मीयर स्लाइड का परीक्षण किया जा सकता था। पीडब्लू-7 ने सभी छह अभियुक्त व्यक्तियों से भी पूछताछ की है और यह भी कहा है कि उनकी पैंट और अंडरवियर को कब्जे में ले लिया गया और सील कर दिया गया और एसएचओ, भदरा को सौंप दिया गया। एस. एच. ओ., भदरा की जांच पीडब्लू-9 के रूप में की गई है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने सरकार के चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त चिकित्सा साक्ष्य के टुकड़े सौंप दिए हैं। अस्पताल, भदरा मलखाना के प्रभारी के पास गया और बाद में उसने परीक्षण के लिए एफ. एस. एल., राजस्थान को भेजे गए आठ पैकेटों में ऐसे सभी साक्ष्य प्राप्त किए और एफ. एस. एल., राजस्थान ने परीक्षण रिपोर्ट (अतिरिक्त। पी-3)

13. एक्स. पी-39, जो दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 293 के तहत रिपोर्ट है। एफ. एस. एल., राजस्थान का सी. लेखों और परीक्षा के परिणाम का निम्नलिखित विवरण देता हैः

"वस्तुओं का विवरण पैकेट पार्सल सं। प्रदर्शनी सं। मेरे द्वारा चिह्नित प्रदर्शनों का विवरण

1 योनि स्वैब

2 योनि स्मीयर

3 सलवार

4 कमीज

5 पैंट्स

6 पैंट्स

7 अंडरवियर

8 पैंट्स

9 पैंट्स

10 अंडरवियर

11 पैंट्स

12 अंडरवियर

13 अंडरवियर

परीक्षण का परिणाम प्रदर्शनी संख्या 1,2 में मानव वीर्य का पता चला, 3,4 (बी से), 5 (1 से), 7 (2 से), 8 (3 से) और 10 (4 से) चिह्नित पैकेट। प्रदर्शनी संख्या 6 (2 से), 9 (4 से), 11,12 (5 से) और 13 (ए से) में वीर्य का पता नहीं चला था। परीक्षा के दौरान प्रदर्शनी संख्या 1,2 (ए से) का सेवन किया गया है। (डॉ. प्रभा शर्मा)

"

14. इस प्रकार, अभियोजक (पीडब्लू-2) का साक्ष्य स्पष्ट है कि सभी छह प्रतिवादी, अकबर, जंगशेर, रोशन, याकूब, कादर और शफी ने उसकी सहमति के बिना और जबरन उसके साथ बलात्कार किया। अभियोजक (पीडब्लू-2) के इस साक्ष्य की पुष्टि सूचना देने वाले (पीडब्लू-1) के साक्ष्य से भी होती है, जिसने खुद अकबर को अभियोजक पर बलात्कार करते देखा था। पीडब्लू-2 ने आरोपी व्यक्तियों द्वारा बलात्कार के तुरंत बाद पीडब्लू-1 को यह भी सूचित किया था कि न केवल अकबर बल्कि अन्य पांच प्रतिवादी ने भी उसके साथ जबरन बलात्कार किया था। पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के साक्ष्य कि सभी छह प्रतिवादी ने अभियोजक पर बलात्कार किया था, की पुष्टि पीडब्लू-1 द्वारा घटना के कुछ घंटों के भीतर पुलिस को की गई शिकायत (Ext.P-1) से

भी होती है जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की खंड 157 में प्रदान किया गया है। डॉ. रामलाल (पीडब्लू-7) ने अभियोजक की चिकित्सकीय जांच के बाद कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चले कि उसके साथ बलात्कार नहीं किया गया था। यह पुष्टि करने के लिए कि क्या छह अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अभियोजक पर बलात्कार किया गया था, योनि के फाहे और योनि स्मीयर के साथ-साथ सा/वार और कमीज व्यक्तियों को पत्र (Ext.P-31) द्वारा एफएसएल, राजस्थान को भेजा गया था और एफएसएल, राजस्थान (Ext.P-39) की रिपोर्ट के अनुसार, योनि के फाहे और योनि स्मीयर (एक्सटीएस) में मानव वीर्य का पता चला था। 1 & 2 पैकेट 'ए' से), अभियोजक का सलवार और कमीज। 3 & 4 पैकेट 'बी' से), दो पैंट (पैकेट 1 से Ext.5, और एक्स्ट। पैकेट 3 से 8) और दो अंडरवियर (पैकेट 2 से Ext.7 और पैकेट 4 से Ext.10)। चिकित्सा साक्ष्य, इसलिए, पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के साक्ष्य की भी पुष्टि करते हैं कि अभियोजक और अभियुक्त व्यक्तियों के बीच यौन संबंध थे।

15. हम प्रत्यर्थी नं. 5 के लिए विद्वान न्यायालय मित्र श्री सिद्धार्थ दवे की इस दलील को प्रतिग्रहण करना नहीं कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष कि अभियोजक अपने दम पर अभियुक्त व्यक्तियों के साथ गया होगा, एक प्रशंसनीय है और संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, अभियोजक (पीडब्लू-2) ने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि सभी छह व्यक्तियों ने उसकी सहमति के बिना और जबरन उसके साथ बलात्कार किया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की खंड 114ए स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि भा.दं.सं. सी. की खंड 376 की उप-खंड (2) के खंड (जी) के तहत बलात्कार के लिए अभियोजन में, जहां आरोपी द्वारा यौन संबंध साबित होता है और सवाल यह है कि क्या यह महिला की सहमति के बिना बलात्कार किया गया था और वह अदालत के समक्ष अपने साक्ष्य में कहती है कि उसने सहमति नहीं दी थी,

अदालत यह मान लेगी कि उसने सहमति नहीं दी थी। चूंकि अभियोजक (पीडब्लू-2) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आरोपी द्वारा उसकी सहमति के बिना और जबरन यौन संबंध बनाए गए थे, इसलिए अदालत को यह धारणा बनानी होगी कि उसने आरोपी व्यक्तियों द्वारा उस पर किए गए यौन संबंध के लिए सहमति नहीं दी थी। बचाव पक्ष ने इस धारणा का खंडन करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है। हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित नहीं कर सकता था कि ऐसी परिस्थितियाँ थीं जो यह दर्शाती हैं कि पीडब्लू-2 अपने दम पर चली गई थी और इस आधार पर प्रतिवादी को बरी कर दिया गया था।

16. एक्स. टी. पी.-39 के साथ पढ़े गए Ext.P-31 से, यह भी है। स्पष्ट करें कि अकबर और जंगशेर की पैंट और सफी और याकूब के अंडरवियर से मानव वीर्य का पता चला था। चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार, चार व्यक्तियों ने अभियोजक पर बलात्कार किया था। भा.दं.सं. की खंड 376 (2) (जी) के स्पष्टीकरण 1 में कहा गया है कि

जहाँ किसी महिला के साथ उनके सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाले व्यक्तियों के समूह में से एक या अधिक लोगों द्वारा बलात्कार किया जाता है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को उप-धारा के अर्थ के भीतर सामूहिक बलात्कार किया हुआ माना जाएगा। इसलिए, इस न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां एक से अधिक व्यक्ति किसी पीड़िता के साथ बलात्कार करने के अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, यह आवश्यक नहीं है कि अभियोजन पक्ष को प्रत्येक अभियुक्त द्वारा बलात्कार के पूर्ण कार्य का प्रमाण प्राप्त करना चाहिए। (ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य [(2011) 14 एस. सी. सी. 309], अशोक कुमार बनाम हरियाणा राज्य [(2003) 2 एस. सी. सी. 143], भूपिंदर शर्मा बनाम एच. पी. राज्य [(2003) 8 एस. सी. सी. 551], प्रदीप कुमार बनाम संघ प्रशासन देखें। [(2006) 10 एस. सी. सी. 608] और प्रिया पटेल बनाम एम. पी. राज्य [(2006) 6 धारा 263])। इस

प्रकार, हम प्रत्यर्थी संख्या के विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश शर्मा की दलीलों को प्रतिग्रहण करना नहीं कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 और 6, और प्रत्यर्थी संख्या 5 के लिए न्यायालय मित्र श्री सिद्धार्थ दवे ने सीखा कि चिकित्सा साक्ष्य भा.दं.सं. सी. की खंड 376 (2) (जी) के तहत सामूहिक बलात्कार का मामला स्थापित नहीं करते हैं।

17. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने सूचनादाता (पीडब्लू-1) की ओर से प्राथमिकी दर्ज करने में देरी को अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह करने के लिए एक प्रासंगिक कारक के रूप में माना है। हम पाते हैं कि पीडब्लू-1 ने अपने साक्ष्य में देरी की व्याख्या की है। उसने कहा है कि जब उसने अपनी बेटी को सुबह लगभग 1 पूर्वाह्न अकबर के साथ भेडिया दफ्तार में पाया और जब पांच अन्य आरोपी भाग गए, तो वे सुबह 2 पूर्वाह्न अपने घर लौट आए और सूर्योदय से पहले तक अपने घर पर रहे और उसके बाद पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने आगे कहा है कि रिपोर्ट दर्ज करने में सुबह 2 पूर्वाह्न से सुबह 6 पूर्वाह्न तक की देरी इस तथ्य के कारण थी कि उनकी पत्नी बीमार थी और वह भी डर गए थे और पुलिस स्टेशन जाने के लिए कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। उसने यह भी कहा है कि वह सुबह लगभग 9 पूर्वाह्न पुलिस स्टेशन से घर लौटा था। भदरा पुलिस स्टेशन के एस. एच. ओ. ने अपने साक्ष्य में कहा है कि 28.04.1999 पर सूचना देने वाला पुलिस स्टेशन में पेश हुआ और उसके सामने एक लिखित रिपोर्ट (Ext.P-1) पेश की। अभियुक्त-रोशन, शफी और याकूब की ओर से जिरह में पीडब्लू-9 ने कहा है कि Ext.P-1 को 28.04.1999 पर सुबह 6 पूर्वाह्न उसके सामने पेश किया गया था। फिर भी उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिपोर्ट (Ext.P-1) लगभग 11.15 बजे दायर की गई होगी। और इसका समय सुबह 6 पूर्वाह्न निर्धारित किया गया था। इस निष्कर्ष के लिए, हमें कोई सबूत नहीं मिलता है, लेकिन केवल एक अनुमान है कि Ext.P-1 अदालत परिसर में सुबह 1 पूर्वाह्न के बाद टाइप किया गया होगा। इस प्रकार, पीडब्लू-1 द्वारा सुबह 6 पूर्वाह्न रिपोर्ट (Ext.P-1) दायर की

गई थी, जिसमें उसने एक घटना देखी थी, जो उसने <आईडी2 पर सुबह 1 पूर्वाह्न से 2 पूर्वाह्न के बीच देखी थी और हमारी राय में, सुबह 2 पूर्वाह्न से 6 पूर्वाह्न तक की अवधि को पीडब्लू-1 द्वारा अपने साक्ष्य में पर्याप्त रूप से समझाया गया है कि वह अपनी पत्नी को सूर्योदय तक अकेला नहीं छोड़ सकता था। जैसा कि डॉ. सिंघवी ने सही कहा है, कोई भी पिता झूठी शिकायत दर्ज नहीं कराएगा कि उनकी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। उच्च न्यायालय को प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के आधार पर अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह नहीं करना चाहिए था।

18. इस प्रकार उच्च न्यायालय का निर्णय अभिलेख पर साक्ष्य के विपरीत है और इसे दरकिनार किया जा सकता है। हम तदनुसार प्रतिवादी को बरी करने वाले उच्च निचली अदालत के फैसले को दरकिनार करते हैं और भा.दं.सं. सी. की धारा 366 और 376 (2) (जी) के तहत अपराधों के लिए प्रतिवादी को दोषी ठहराने वाले निचली अदालत के फैसले को बहाल करते हैं और निचली अदालत द्वारा प्रतिवादी पर लगाए गए दो अपराधों के लिए सजा को बनाए रखते हैं।

19. तदनुसार अपीलों की अनुमति दी जाती है। शेष सजा भुगतने के लिए प्रतिवादी को तुरंत हिरासत में ले लिया जाएगा।

आर. पी. अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।